

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ०प्र०,  
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ  
सामान्य वर्ग

12/07/21

पत्रांक 8457 एम०टी०/सामान्य वर्ग/54एम०-471/2019

दिनांक : 12/07/2021

कार्यालय-ज्ञाप

आपका लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० में मार्ग कार्य हेतु श्रेणी 'ए' की ठेकेदारी में पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक-17067एम०टी०/सामान्य वर्ग/54एम-471/2019, दिनांक 20.11.2019 द्वारा दिनांक 30.06.2022 तक के लिए किया गया।

उक्त पंजीकरण के समय फर्म के सोल प्रोपराइटर श्री जय प्रकाश सिंह पुत्र श्री कमला सिंह, भीटी, मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ का जिलाधिकारी, मऊ के पत्र सं०-082/शि०लि०-मऊ/2017-18, दिनांक-14.07.2017 द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर इस कार्यालय के उपरोक्त पत्र दिनांक-20.11.2019 द्वारा दिनांक-30.06.2022 तक मार्ग कार्यों के श्रेणी 'ए' में पंजीकरण किया गया है। जिलाधिकारी, मऊ ने अपने पत्र सं०-307/शि०लि०/20, दि०-04.06.2020 द्वारा श्री जय प्रकाश सिंह पुत्र श्री कमला सिंह, भीटी, मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ को निर्गत उक्त चरित्र प्रमाण पत्र को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

उक्त प्रकरण में इस कार्यालय के पत्र सं०-13861एम०टी०/सा० वर्ग/54एम०-471/2019, दिनांक-10.11.2020 द्वारा कारण बताओ नोटिस ठेकेदार को निर्गत किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर फर्म/ठेकेदार के पत्र दिनांक-शून्य जो इस कार्यालय में दिनांक-25.11.2020 को प्राप्त हुआ पर मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ क्षेत्र, लो०नि०वि० आजमगढ़ को इस कार्यालय के पत्र सं०-14762एम०टी०/सा० वर्ग/54एम०-471/2019, दिनांक-10.12.2020 द्वारा उत्तर का परीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी, मऊ ने अपने पत्र सं०-307/शि०लि०/20, दिनांक-04.06.2020 श्री जय प्रकाश सिंह, मोहल्ला-भीटी, थाना-कोतवाली नगर, जनपद-मऊ के चरित्र प्रमाण पत्र हेतु किए गए आवेदक को पुलिस अधीक्षक की आख्या दिनांक-05.12.2020 के अनुसार पंजीकृत मुकदमा अपराध सं०-144/2019 धारा 419/420 भा०द०वि० में वाद विवेचना जरिए अन्तिम रिपोर्ट मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जो विचाराधीन न्यायालय है, को चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाना विधि सम्मत नहीं है। तदनुसार प्रत्यावेदन दिनांक-08.02.2021 निरस्त किया गया है तत्क्रम में शासन के पत्र सं०-366/तेइस-7-2021, दिनांक-22.03.2021 द्वारा भी प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

उपरोक्त प्रकरण में जिलाधिकारी, मऊ द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाना विधि सम्मत न होने के कारण तथा प्रकरण मा० न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण शासनादेश सं०-2365/एम०एस०/23-पी० डब्लू०-41एम० एस०/1954, दिनांक 24.08.1982 एवं प्रमुख अभियन्ता, उ०प्र०, लो०नि०वि०, लखनऊ के पत्र सं०-362 एम०टी० जी०/70 एफ-68, दिनांक 08.10.1982 द्वारा निर्गत ठेकेदारों के लिए वर्गीकरण एवं पंजीकरण नियमावली एवं पंजीकरण से सम्बन्धी सुसंगत शासनादेशों एवं शासनादेश सं०-4127 एम० एस०/23सा० नि०अनु०(7), दिनांक 02.12.1974 के अन्तर्गत मा० न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक उक्त फर्म/ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त करते हुए डिबार किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किए जाते हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

उक्त आदेश प्रमुख अभियन्ता(परि०/नियो०), लो०नि०वि० उ०प्र० के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

12.7.21

(वी० के० जैन)

मुख्य अभियन्ता (मु०-2).

लो०नि०वि०, लखनऊ